लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

# हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1 - 15 अगस्त, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 71

"दूसरों की निंदा करने में अपना समय बर्बाद न करें।

: शेक्सपियर

हर घर नल से जल

3

करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

4

जीओ गीता ऐप का हुआ शुभारंभ

8

# बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी मनोहर सरकार

» मृतक के परिवारों को चार-चार लाख की मदद

» गिरदावरी के तुरंत बाद मिलेगा फसल मुआवजा

विशेष प्रतिनिधि

अनुमान से अधिक हुई बरसात से प्रदेश के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। जहां जिस क्षेत्र में बरसात ज्यादा नहीं हुई वहां के खेतों व आबादी देह में भी बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। जान-माल के नुकसान के साथ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य की मनोहर सरकार इस प्राकृतिक आपदा के प्रति काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। हर दुख-दर्द को साझा करते हुए सरकार की ओर से हर संभव मदद दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के 8 जिलों में 35 मृतक लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए सहायता राशि दी गई है। यह मदद राशि आरटीजीएस से सीधे खाते में पहुंची। परिवार पहचान पत्र के जरिए हर परिवार का डाटा वैरिफाई होता है जिसके तुरंत बाद मुआवजा राशि उपलब्ध करा दी जाती है। प्रदेश में बाढ़ से कुल 1463 गांव प्रभावित हुए हैं जबकि इस आपदा में मरने वालों की संख्या करीब 40 है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक बरसात का पानी उतर जाने के बाद प्रभावित क्षेत्र के किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की ओर से राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं। सेना, वायुसेना, एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ की मदद ली गई है।

गौरतलब है कि पानी की मार को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर शामिल हैं। इनमें 1353 गांव और 4 शहरी क्षेत्र बारिश व बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी अत्यधिक भारी वर्षा हुई। जिससे राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई।

किसानों को आह्वान किया गया है कि वे 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर अपनी पूरी खेती योग्य जमीन का पंजीकरण अवश्य कराएं। पोर्टल के आधार पर टीम वहां का सर्वे करेगी और मुआवजा तय करेगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर 7 दिन में वेरिफाई किया जाएगा, इसके बाद मुआवजा दिया जाएगा।

प्रदेश में 1142 कि.मी लंबी 996 सड़कें प्रभावित हुई हैं जिनकी मरम्मत के लिए 230 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।

**यमुना पर बांध बनाने की योजना**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हथनीकुंड बैराज से 500 मीटर पीछे बांध बनाने के प्रस्ताव पर हिमाचल सरकार के साथ बात चल रही है। जल्द ही इस पर निर्णायक रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारी बारिश के दौरान टांगरी नदी के ओवरफ्लो होने को गंभीरता से लेते हुए नदी के दूसरी तरफ भी पक्का तटबंध बनाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

# सुशासन के लिए आगे आएं सहयोगी

प्रदेश की मनोहर सरकार विकास कार्यों को लेकर पूरी गति पर है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय तक अनेक योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वैसे भी शुरू से प्रयास रहा है कि प्रदेश की जनता को वे तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिनसे वे आज तक महरूम रही। इसके लिए उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन करने का संकल्प लिया और पूरी प्रतिबद्धता के साथ शासकीय एवं प्रशासकीय अमले की तयशुदा जिम्मेदारियों के साथ लक्ष्य हासिल करने का काम किया।

जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की सही-सही जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकाल के साढ़े आठ साल बाद खुद जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। इसके लिए शुरू किया गया 'जन संवाद' कार्यक्रम सफल हो रहा है। कुछ जमीनी समस्याओं एवं शंकाओं को जानने का मौका मिला है। इनके निवारण के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं।

अफसरों को कहा गया है कि वे आम लोगों के पास जाएं और उनसे बातचीत करें। इस कार्य में सुशासन सहयोगियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। सुशासन सहयोगी सरकार व जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। सहयोगियों को और अधिक मुखरता के साथ काम करने के लिए कहा गया है। विभागीय स्तर की परेशानियों को राज्य सरकार तक पहुंचाना व उनका तत्परता से समाधान करना होगा। किसी भी विभाग से संबंधित फाइलें लंबित न रहें इसका भी ध्यान देना होगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से मिलकर कार्य करें और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से सरकार को अवगत करवाएं।

जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनकी जानकारी लेना और कौनसी पद्धति अपनाकर आम जन को लाभ मिल सकता है, के बारे में सुशासन सहयोगियों को और अधिक गंभीरता से सोचना होगा।

गौरतलब है कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14039 समस्याओं मे से 13730 को मार्क कर अपलोड कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ जल्द ही आगामी बैठक की जाएगी। उस बैठक में प्रगति रिपोर्ट को टेबल फोरम में लक्ष्य और दिनांक सहित विस्तार से लेकर आने के लिए कहा गया है, जिससे सारगर्भित समीक्षा की जा सके।

**-संवाद ब्यूरो**

## भ्रष्टाचार पर सख्ती

मनोहर सरकार द्वारा शुरू की गई भ्रष्टाचार मुक्त कामकाज की परिपाटी से आम लोग खुश हैं, जबकि विपक्ष परेशान है। विपक्ष राज्य सरकार के कामकाज से इतनी परेशान नहीं है, जितनी परेशानी लोगों की खुशी से है। विपक्ष का मानना है कि अगर लोग परेशान नहीं होंगे तो राजनीतिक बदलाव कैसे होगा ? यही वजह है कि कुछ लोग सरकार के कामकाज में कमियां निकालने का प्रयास करते रहते हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार के समय तीन सी ' क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला था। उन्होंने इन तीनों में सुधार कर दिया।

अपराध पर अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और जातिवादी राजनीति को समाप्त करने का काम किया। प्रदेश में जब से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, तब से 30 से 40 प्रतिशत ज्यादा काम उसी राशि से ज्यादा हुए हैं।

लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पोर्टल और ऐप बनाई हैं। कुछ नेता मजाक में कहते हैं कि यह पोर्टल की सरकार है, हम स्वीकार करते हैं कि यह पोर्टल की सरकार है। वास्तविकता यह है कि यदि हम 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनाते तो लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

यही उन नेताओं की परेशानी है कि घर बैठे सुविधाएं तथा लाभ मिलेगा तो फिर सुविधा शुल्क का खेल कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब समझ रही है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता कहेगी कि पोर्टल की सरकार से जीवन में सहजता व सरलता आई है। प्रशासनिक व नेताओं के कार्यालय में धक्के नहीं खाने पड़ते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति करने वाले कुछ लोगों का मुफ़्त बांटने में विश्वास है। जबकि उनकी सरकार का लक्ष्य लोगों को रोजगार देना है। लोग कमाकर खाएंगे तो स्वाभिमानी जीवन जीएंगे। मांग कर या मुफ़्त लेकर जीवन जीना अच्छी बात नहीं है।

**-मनोज प्रभाकर**

संपादकीय

## 8 साल में 31 कॉलेज सिर्फ़ बेटियों के लिए

यह एक अनूठी मिसाल है। गत आठ साल में 72 सरकारी कॉलेज खुले और उनमें भी 31 कॉलेज बेटियों के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगतिशील सोच के कारण उच्च शिक्षा को लेकर भी हरियाणा ने गंभीरता के साथ काम किया है। हरियाणा प्रदेश में कुल 179 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 74 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं जिनमें से 31 राजकीय महाविद्यालय केवल 'म्हारी' बेटियों के लिए हैं।

नई दिशा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहां लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 32 प्रतिशत है। यह भी तय है कि हम 2030 से बहुत पहले ही 50 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शिक्षा-ऋण के तीन महीने के ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय भी सरकार की तरफ से किया गया है। विश्वविद्यालय या कॉलेजों में विवाहित छात्राओं को 45 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है।

इस सरकार ने जो वादे किए वह पूरे कर दिखाए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को जो सरकारी नौकरी का वादा किया था वह पूरा कर दिया है। बिना किसी सिफारिश के मेहनती व काबिल लोगों को नौकरी दी गई है। लगभग एक लाख अधिक लोगों को अब तक सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक राज्य के पौने दो लाख लोगों को नौकरी देना है। इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने नौकरी में भाई भतीजावाद खत्म कर काबिल लोगों को नौकरी दी है।

**कुछ अन्य प्रभावी योजनाएं**

» हरियाणा सरकार कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे प्रदेश की जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिना दफ्तरों के चक्कर काटे लाखों परिवारों के बीपीएल कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रदेश के परिवारों को मुफ्त दिया जा रहा है।

» प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना व चिरायु योजना के तहत बीपीएल परिवारों को सालाना पांच लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। साथ ही 541 प्रकार की दवाइयां व 379 प्रकार के उपभोग्य सामग्री, कोविड वस्तुएं व डेंटल आइटम की सुविधाएं मुफ्त मुहैया करवाई जा रही हैं।

» प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर 10467 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। डायल 112 हर संकट में साढे आठ मिनट में मदद मिल रही है।

» 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत 5743 गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी गई है।

» ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच को दर्शाती हैं।

**-डॉ. चन्द्र त्रिखा**

# सरकार आपके द्वार

नई दिल्ली: विगत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं तथा प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय में बातचीत की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों, योजनाओं व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का फीडबैक आमजन से लेने की नई पहल करते हुए 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा वार प्रबुद्ध व्यक्तियों से धरातल पर हो रहे कार्यों की सीधी जानकारी लेना शुरू की है।

मुख्यमंत्री इन दिनों उच्चाधिकारियों व विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ जन समस्याओं का मौके पर ही निवारण करने का प्रयास कर रहे है। जुलाई के अंत तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रयास रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में आमतौर पर यह शंका रहती है कि चंडीगढ़ मुख्यालय में अधिकारी फाइल देरी से क्लीयर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। सीएमओ में आए हर कागज की तहकीकात होती है। कोई कागज बिना पढ़े नहीं रहता। इतना ही नहीं, पत्र भेजने वाले को उसकी मांग व समस्या के बारे सूचित भी किया जाता है।

मनोहर लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध व्यक्ति सरकार की योजनाओं व सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचायें, ताकि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे पात्र नागरिकों को सबसे पहले योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

## महिलाओं को स्वरोज़गार के लिए ऋण योजना

हरियाणा सरकार द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया गया है।

निगम द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। निगम द्वारा महिलाओं को विभिन्न कार्यों जिसमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार ईकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कार्य शुरू कर सकती हैं। इन कार्यों के लिए महिलाओं को ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने कारोबार को बेहतर ढंग से आरंभ कर सकें। इस ऋण योजना के तहत जिन विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तथा आयु 18 से 55 वर्ष है वे इस योजना के तहत पात्र होंगी।

इस योजना के तहत जिले में 60 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल राशि का दस प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंक के माध्यम से दी जाएगी। योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। अनुदान की अधिकतम राशि 50,000 रुपए तथा अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी लागू की जाएगी। उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।

**सलाहकार संपादक :** डा. चंद्र त्रिखा
**सह संपादक :** मनोज प्रभाकर
**स्टाफ राइटर :** संगीता शर्मा
**संपादन सहायक :** सुरेंद्र बांसल
**चित्रांकन एवं डिज़ाइन :** गुरप्रीत सिंह
**डिजिटल सपोर्ट :** विकास डांगी

## योग मानस
### योग के जरिए करें उपचार

आजादी के अमृत महोत्सव की शृंखला में हरियाणा आयुष विभाग की ओर से 'योग मानस' (योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सिस्टम) ऐप की शुरुआत हो चुकी है। शरीर को स्वस्थ रखने और योग के जरिए उपचार करने में यह ऐप सहायक सिद्ध होगी।

आयुष मंत्री अनिल विज ने इस उपयोगी ऐप की शुरुआत की थी। उन्होंने स्वयं इस ऐप पर अपने आप को पंजीकृत किया है। सेहत की देखभाल व संतुलित जीवन जीने के लिए योग की जीवन में बहुत महत्ता है। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों की योग गतिविधियों, योग सहायकों द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही इत्यादि पर निगरानी रखी जा सकेगी।

ऐप के माध्यम से योग में भाग लेने के लिए नागरिक अपने मोबाइल से पंजीकरण कर सकता है। यह ऐप गुगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में जिला आयुष अधिकारी का लॉगइन दिया गया हैं तथा योग सहायक के माडयूल के साथ-साथ डैशबोर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से योग की गतिविधियों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नजर रखी जाती है।

इसी प्रकार से योग सहायकों की अलग से लॉगइन प्रक्रिया है। योग सहायक को अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन करनी होगी और अपनी योगशाला का चयन करना होगा। उसके पश्चात उसे अपने बैच का सृजन करना होगा तथा उसके बाद बैच की जानकारी दिखाई देगी।

इस एप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार के योग के आसनों की सूची भी दी गई हैं जिसे नागरिक अपने अनुसार कस्टमाइज कर पाएगा। एप्लीकेशन में जिला आयुष अधिकारी का लॉगइन भी दिया गया है जिससे वह योगशाला, योग सहायक, योग सत्रों सहित सब्सक्रिप्शन की निगरानी कर सकेगा।

### ऐप अवश्य डाउनलोड करें: डा. साकेत

आयुष विभाग के महानिदेशक डॉ साकेत कुमार ने बताया कि प्रतिभागी को अपने मोबाइल में योग मानस एप्लीकेशन को इंस्टाल करना चाहिए। उसके बाद नागरिक को अपनी बेसिक जानकारी डालकर इसे चालू करना होगा। ऐप चालू होने के बाद जीपीएस के माध्यम से नागरिक के आसपास की योगशालाओं की लोकेशन दिखाई देगी। प्रतिभागी अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित योगशाला में अपना पंजीकरण करने पर अपने सत्र को सब्स' इब करेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात प्रतिभागी का एनरोलमेंट हो जाएगा। नागरिकों से अपील की जाती है कि वे इस योग मानस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें ताकि योग के जरिए होने वाली चिकित्सा का पूरा फायदा लिया जा सके।

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या उसके समकक्ष करने का निर्णय लिया है।

'आयुष्मान भारत योजना' में पहले प्रदेश के 15 लाख परिवार कवर हो रहे थे, लेकिन 'चिरायु हरियाणा योजना' के बाद अब प्रदेश में यह संख्या 30 लाख हो गई है।

# हर घर नल से जल

## प्रदेश के 29 लाख घरों में पहुंची पेयजल सप्लाई

मनोज प्रभाकर

नदियों को यूं ही नहीं 'मां' का कहा जाता । इस मां ने विश्व की तमाम सभ्यताओं की पालना की है। जितने भी पुराने शहर अथवा अन्य घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं, वे सभी नदियों के किनारे फले-फूले हैं, विकसित हुए हैं। नदियों को सम्मान देने की परंपरा में आज भी हम सब उनकी पूजा अर्चना करना नहीं भूलते हैं।

यही वजह है कि हमारे ऋषि-मुनियों व संत-महात्माओं ने मानव के अस्तित्व के लिए जल के संरक्षण पर बल दिया है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पानी की कमी प्रदेश के विकास में बाधा न बने। हमारी पीढ़ियों को पानी की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए हम सभी को पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग करना होगा। इसी बात को अहमियत देते हुए हरियाणा जल जीवन मिशन के तहत हर घर-नल से जल पहुंचाने वाला पहला बड़ा राज्य बना है। केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा था, जिसे हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही पूरा करने का काम किया है। कुल मिलाकर लगभग 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा से 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम के लाथार्थियों से सीधा संवाद किया।

लाभार्थियों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जब से घरों में नल से पानी मिल रहा है, तब से उनका जीवन बेहतर बना है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। लाभार्थियों ने कहा कि यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि उन्हें कभी दूर-दराज से पानी लाने से मुक्ति मिलेगी। मनोहर सरकार ने हमें यह सहूलियत प्रदान करके बहुत बड़ा उपकार किया है।

मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना हम सबका अधिकार है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करवाने तथा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद-बूंद को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवदेनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। उनके इसी विचारों पर चलते हुए हरियाणा सरकार जल संरक्षण के लिए प्रदेश की जनता को जागरुक करने का काम कर रही है।

राज्य सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 271 नहर आधारित जल घर तथा 229 नलकूप आधारित जल घर स्थापित किये हैं। 1,457 करोड़ रुपए की लागत से 4,774 नलकूप तथा 1,246 बूस्टिंग स्टेशन भी स्थापित किये हैं। इनके अलावा, 3,299 करोड़ रुपए की लागत से 19,515 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। महाग्राम योजना के तहत 31 बड़े गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्रोतों में वृद्धि तथा मल-निकासी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य किये गये हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे गांव में जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए काम करें।

# सेहत को लेकर हो जाएं सावधान

बरसात के बाद अक्सर मच्छर जनित बिमारियों का प्रकोप देखा जाता रहा है। इस बार बरसात औसत से अधिक हुई है जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात का पानी खेतों, गड्ढों व खाली पड़ी जमीनों में अधिक दिनों तक रहेगा। पानी ठहरहेगा तो मच्छर भी पैदा होंगे। वैसे भी हर बरसात के सीजन के बाद डेंगू, टाइफायड, चिकनगुनिया जैसे बुखार व पेट से संबंधी रोग होते हैं। सितंबर व अक्तूबर के माह में अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की लंबी लाइन रहती है। यह स्थिति उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में होती रही है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इन रोगों के बारे में आम लोगों को जागरूक होना निहायत जरूरी है। कम्यूनिटी विभाग के डा. आर बी जैन के मुताबिक इन दिनों में पेयजल की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की जरुरत होती है। जहां कहीं भी पानी की शुद्धता पर शक हो तो उसे या तो न पीएं या फिर उबालकर पीएं। इन दिनों में पेयजल में क्लोरिन की दवा मिलाने की भी सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि 20 लीटर पानी में क्लोरिन की एक गोली डाल दें। उसके आधा घंटा बाद यह पानी पीने योग्य माना जाता है। इन दिनों में कटे व सड़े गले फल अथवा सब्जी तो कदापि न लें। इनसे भी पेट संबंधी रोग जैसे दस्त, हैजा या बुखार होने की आशंका बनी रहती है।

इस तरह की जागरूकता के लिए हर आदमी को सावधान रहना होगा। केवल स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे न रहें तो बेहतर होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन दिनों अपने स्तर पर सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास करता है लेकिन अपने घर पर या आस पड़ौस में सफाई रखने की जिम्मेदारी तो सभी लोगों की होती है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से सलाह दी जाती है कि कोई भी परिवार अपने आसपास पानी न खड़ा होने दे, कूलर में पानी डालना बंद करें, क्योंकि इन दिनों में कूलर की आवश्यकता नहीं होती। केवल पंखों की हवा से काम चल सकता है। कूलर में अगर पानी पड़ा है तो उसे बाहर करें क्योंकि कूलर में अक्सर मच्छरों का बसेरा होता है। इसके अलावा फ्रिज के पीछे की एक कटोरी नुमा बर्तन में कुछ पानी होता है उसे नियमित रूप से साफ करते रहें। मच्छर या गंदगी कहीं हो सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रख पाएंगे।

मेडिसन के डा. गजराज कौशिक ने कहा कि इन सब तरह की सावधानियों के बावजूद भी अगर परिवार के किसी सदस्य को बुखार हो जाए तो उसे निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में ले जाएं। उसकी जांच कराएं और उचित उपचार लें। उन्होंने आगाह किया कि इन दिनों में ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना भी सेहत पर भारी पड़ सकता है, इसलिए इनका सेवन न करें।

**– संवाद ब्यूरो**

### प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाएः मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर चिकित्सा के समुचित प्रबंध किये गए हैं। मेडिकल कैंप लगाये गये हैं जहां मरीजों की जांच एवं उपचार किया जा रहा है। आवश्यक दवाइयां व ओआरएस के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एहतियात के तौर पर विभाग द्वारा गांवों में फोगिंग करवाई जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की वे सावधानी बरतें। पानी उबालकर पीएं। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। बीमारी का कोई लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।



राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से थाने बनाएं हैं। वर्ष 2014 में सोनीपत में केवल एक महिला थाना था, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 29 महिला थाने हैं।




ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरियाणा की पचास फीसद हिस्सेदारी है। जीएसटी कलैक्शन में हरियाणा नंबर-1 है। लगातार उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जिससे रोज़गार के अवसर भी बढ़े हैं।

# प्रगति के करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

संगीता शर्मा

प्रदेश की मनोहर सरकार प्रगति की पटड़ी पर सरपट दौड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इतना ही नहीं करोड़ों रुपए के नए विकास कार्यों का एलान भी किया जिन्हें आने वाले एक या दो वर्ष में पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की अनेक सौगात दी हैं। नूह जिला के फिरोजपुर झिरका में 2,741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1,270 करोड़ रुपए की लागत की 157 परियोजाओं का उद्घाटन तथा 1,462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर झिरका में नूह की भी 305 करोड़ रुपए की नौ परियोजनाओं को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने नूह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, नूह से मुंडाका गांव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। यह कार्य नवंबर तक शुरू होने हो जाएगा। इसके अलावा, फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलसीपीडी करने की भी घोषणा की। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साढ़े आठ सालों से चली आ रही विकास की गति को आज की परियोजनाओं ने ऐतिहासिक बना दिया है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डिजिटल माध्यम से छह बार पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है, जिससे लगभग साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए की लागत की 1,100 से अधिक परियोजनाएं जनता को दी गई हैं। आज की परियोजनाओं की 2,741 करोड़ रुपए की लागत जोड़ने पर यह लगभग 15 हजार करोड़ हो जाती है। इस तरह डिजिटली एक ही स्थान से इतने व्यापक स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करना ई-गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है, इससे समय और पैसे की बचत हुई है। रैनीवेल आधारित पेयजल योजना नूह के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा। दिल्ली मुंबई कोरिडोर नूह से निकलता है। इस कॉरिडोर के कारण इस इलाके में उद्योग लगेंगे जिससे नौजवानों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।

### रोजगार के अनुकूल माहौल

प्रदेश सरकार ने छह एस - शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन पर जोर दिया है। हरियाणा में हर व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित समझता है और इसका ही परिणाम है कि आज दुनिया के लोग निवेश करने के लिए हरियाणा की तरफ देखते हैं। हरियाणा उनका पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े आठ सालों में सरकारी नौकरी के तौर पर प्रदेश में एक लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। इन सरकारी नौकरियों को मिलाकर प्रदेश में कुल 35 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, जो देश में 2,750 रुपए की सर्वाधिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है और शीघ्र ही इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा।

### फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं

राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। अभी तक 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर किसान अपनी उसी फसल का पंजीकरण करवाते थे, जो बाजार में बिकती थी या खराब होने पर उसका मुआवज़ा ले पाएं। लेकिन इस प्रणाली में कुछ गड़बड़ी पाई गई। कुछ खाली ज़मीन रहती थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। आस-पास के प्रदेश जैसे राजस्थान व पंजाब से लोगों ने खाली ज़मीन पर रजिस्ट्रेशन दिखाकर हमारे यहां फसल बेचना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी हर एक एकड़ ज़मीन का पंजीकरण करवाएं। यहां तक की खाली ज़मीन का भी पंजीकरण अवश्य करवाएं।

## गुरुग्राम ड्रेनेज सिस्टम होगा बेहतर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गुरुग्राम जिला में 237 करोड़ 50 लाख 5 हजार 187 रुपए की लागत की 34 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर उन्हें आमजन को समर्पित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में नूह के फिरोजपुर झिरका में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला में जीएमडीए द्वारा वाटिका चौक, सोहना रोड से एनएच 48 तक व एसपीआर पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए लेग चार के निर्माण से शहर में होने वाले जलभराव में करीब 20 प्रतिशत की राहत मिलेगी।

परियोजनाओं में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 144 करोड़ की तीन परियोजनाएं शामिल हैं। कृषि मंत्री ने नगर निगम, मानेसर की 66 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 28 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

### यमुनानगर में 12 परियोजनाएं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के अमृत काल में यमुनानगर जिला को करीब 27 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से होने वाले 17 जनहितकारी परियोजनाओं के विकास कार्यों की सौगात दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम यमुनानगर के जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया। जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने 12 परियोजनाओं का उद्घाटन व पांच का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ही दिन में 2,741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया है।

### कुरुक्षेत्र को सात परियोजनाओं की सौगात

हरियाणा के मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र के नागरिकों को एक साथ 22.77 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सात बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने का काम किया है। इस सौगात के तहत छह परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और एक परियोजना का उद्घाटन किया है।

लोक निर्माण विभाग की 3.10 करोड़ रुपये की लागत से पिहोवा रोड से खेड़ी मारकंडा और सिरसला कनीपला रोड, 69.42 लाख रुपए की लागत से पुराना बाईपास मार्ग, 24.42 लाख की लागत से पिपली में कुरुक्षेत्र रोड से सिरसला और शादीपुर सड़क, केडीबी के 1.35 करोड़ रुपए की लागत से सन्निहित सरोवर पर लगने वाली महर्षि दधीचि की प्रतिमा के निर्माण कार्य, केडीबी के ही 1.38 करोड़ रुपए की लागत से सोमेश्वर तीर्थ गुमथला गढु के निर्माण कार्य, सिंचाई विभाग की 7.45 करोड़ रुपए की पटेल नगर, हरिगढ़ भोरख से जोधपुरा-जंदेड़ी पर बनने वाले पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया तथा 8.55 करोड़ रुपए की लागत से नरवाना ब्रांच सिंगल स्पेन स्टील से बने पुल का उद्घाटन किया।

### फतेहाबाद में देवेंद्र बबली ने किया उद्घाटन

फतेहाबाद में पशुपालन विभाग की छह और महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया गया। पशुपालन विभाग के गांव लाली, दादुपुर, कलां व माजरा में 35.83 लाख रुपए (प्रत्येक), गांव फुलां व रत्ताखेड़ा में 32.83 लाख रुपए (प्रत्येक) की राशि से निर्मित राजकीय पशु चिकित्सालय तथा 25.32 लाख रुपए की राशि से निर्मित महिला एवं बाल विकास विभाग की वन स्टॉप सेंटर-सखी का उद्घाटन किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शिरकत करते हुए इन विकास परियोजनाओं को जिले को समर्पित किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से काम करते हुए विकास परियोजनाओं को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए नए कार्य आरम्भ किए गए है। उन्होंने कहा कि पंचायतें, जिला परिषद, ब्लॉक समितियों के विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है और सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है।

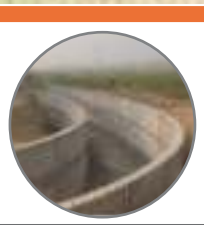



मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के साथ-साथ तैयार की गई आरसीसी पैरलल ड्रेन के रख-रखाव का जिम्मा हरियाणा सरस्वती बोर्ड को देने के निर्देश दिए हैं।

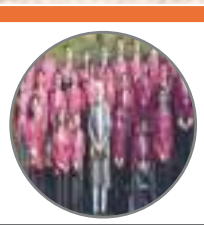



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 की है। आवेदन प्रक्रिया पोर्टल डु2डुह्स्रह्य. द्गश्1.द्बठ्ठ पर शुरू हो गई है।

# नए आयाम

## आर्थिक विकास को गति देगी पानीपत रिफाइनरी

वर्ष 1998 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिली है। इसकी स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन है। इंडियन ऑयल ने इस रिफाइनरी के लिए आने वाले वर्षों में 25 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर 35 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विस्तार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रिफाइनरी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। विस्तार के लिए रिफाइनरी के आसपास के तीन गांवों पाल जाटान, खंडवा और आसन कलां की पंचायतों से बात हुई है और उन्होंने ऑफर किया है कि वे लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन इंडियन ऑयल को देने के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहे।

### रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे

रिफाइनरी द्वारा पानीपत में 7,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, रिफाइनरी की ओर से यहां दैनिक 1000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। आगामी वर्षों में आने वाली तथा जारी परियोजनाओं पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे।

मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में तकनीकी विकास के साथ-साथ, आज यह भारत का सबसे बड़ा एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल प्लांट बन गया है। इस रिफाइनरी द्वारा हरियाणा में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

### देश की विकास यात्रा में योगदान

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा देश की विकास यात्रा में विशेष योगदान दे रहा है। हरियाणा न केवल एक गौरवशाली व पवित्र धरा है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि, देशभक्ति, उन्नति और विकास के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में इंडियन ऑयल पानीपत रिफायनरी 7,000 टन क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने जा रहा है। इस पर 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस मेगा परियोजनाओं से हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास में बहुत तेज़ी आएगी।

## आइडिया व तकनीक से खुलते रोजगार के नए आयामः मनोहर लाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि विज्ञान की ऐसी प्रगति होगी। पहले डाक थी, अब ई-मेल से तुरंत डाक पहुंच जाती है। अपने कार्यालय का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए चैटजीपीटी के माध्यम से पांच मिनट में ही जो बोला गया वह टाइप होकर मिल गया। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीकों से बेहतर कार्य हो रहा है। अब युग बदल रहा है। आज नये विचार आ रहे हैं। स्टार्टअप से युवाओं को उद्योगों की ओर अग्रसर होने के अवसर मिल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में यही शामिल है कि शिक्षा रोज़गारपरक होनी चाहिए और हुनर को बढ़ावा मिले। अब पुरानी थ्री-आर (रीडिंग, राइटिंग, अर्थमैटिक्स) वाली शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शून्य से हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस स्थापित हुए हैं। सिर्फ़ आईडिया के बल पर लोग व्यवसाय में इतनी आगे पहुंचे।

### अटल अकादमी लोकार्पित

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 46 लाख रुपए की लागत से दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में स्थापित 135 फीट ऊंचे तिरंगे का आरोहण करते हुए कहा कि इससे देशभक्ति की भावना को बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने 35 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अटल अकादमी एवं आइडिया लैब को भी लोकार्पित करते हुए विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसीआरयूएसटी में सबसे पहले सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है, जो एक गौरव एवं प्रेरणादायी परियोजना है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं वास्तुकला को समर्पित अटल अकादमी एवं आईडिया लैब से शोध को बढ़ावा मिलेगा। डीसीआरयूएसटी के नाम में ही विज्ञान शामिल है, जो विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इस परियोजना में एआईसीटीई का विशेष रूप से सहयोग मिला है। आईडिया लैब की स्थापना से नए-नए विचारों को विकसित कर विज्ञान के माध्यम से जीवनशैली में उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी।

## प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करेंगी मशीनें

हरियाणा सरकार राज्य के हर ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण मशीनें लगाने का कार्य कर रही है। इनमें प्लास्टिक श्रेडर, बेलिंग मशीन और धूल हटाने वाली मशीनें शामिल हैं, जिन्हें लगभग 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से लगाया जाएगा। इन इकाईयां से रिसाइक्लिंग की सुविधा आसान होगी और प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भी कमी आएगी। 1 जुलाई, 2022 से 31 मई, 2023 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य योजना के तहत 17,407 चालान काटे गए। राज्य भर में 15,045 किलोग्राम एकल-उपयोग प्लास्टिक जब्त करके उन पर 1,46,62,750 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण स्तर पर जनता को ज़ागरूक करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार गतिविधियों को बढावा देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। प्लास्टिक अपशिष्ट नियमों की विस्तार से समीक्षा की और एकल प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से अधिग्रहित मशीनें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट प्लास्टिक बैग, बोतल, पैकिंग आदि का सही प्रोसेस करेंगी। यह मशीनें राज्य को प्लास्टिक मुक्त करने में अहम कदम साबित होगी।

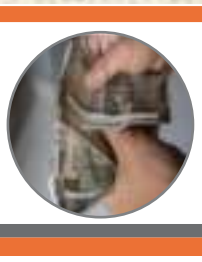

हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा।

हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बच्चों को दिए टैबलेट का इस्तेमाल अधिक से अधिक करवाया जाए। बच्चों को टैबलेट पर असाइनमेंट दिया जाए।

# हरियाणा में कृषि की अनुकरणीय योजनाएं

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं हेतु अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसान हित में उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमों को देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में लिए जा रहे निर्णयों से अवगत कराया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तोमर से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में लागू की गई योजनाओं का लाभ हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को प्रभावी ढंग से पहुंचा रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान हित में हरियाणा सरकार की नीतियों को पूरे देश के लिए आदर्श बताते हुए उन्हें हर संभव सहयोग दिए जाने का विश्वास दिलाया। तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों व उनके लाभ के लिए सजग एवं सतर्क है, ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के किसान हित में उठाए जा रहे निर्णय में वे निरंतर सहयोगी रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य जिसमें 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल के माध्यम से किसानों की कृषि योग्य बोई गई फसलों का संपूर्ण डाटा रिकार्ड किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी रूप से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खेत की बुआई करने वाले किसान को प्रभावित हुई फसल का मुआवज़ा समय पर दिया जाए।

### बीमा योजना में तकनीकी खामियों से अवगत कराया

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से संबंधित किसानों को आ रही तकनीकी कठिनाईयों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की संतुष्टि हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के समक्ष वे विभिन्न सुझाव रखते हुए समाधान करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी रूप से किसानों को कोई असुविधा न हो इसके लिए हर स्तर पर सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की बागवानी फसलों पर भी सरकार का पूरा फोकस है और हरियाणा में 'भावांतर भरपाई योजना' के माध्यम से भी किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है।

**-संवाद ब्यूरो**

# मत्स्य पालन को और बढ़ावा देगी सरकार

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2023 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में महाबलीपुरम, तमिलनाडू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण व मत्स्य पालन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दलाल ने हरियाणा में मत्स्य पालन गतिविधियों की विस्तार से जानकारी देते हुए मत्स्य पालन के क्षेत्र में आ रही दिक्कतों के निवारण के लिए केंद्रीय मंत्री से सहयोग करने का आग्रह किया।

जे.पी दलाल ने कहा कि हरियाणा में 16 हजार मत्स्य पालक किसान हैं और 45 हजार एकड़ में मछली पालन किया जाता है। परिणामस्वरूप 2.12 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। 5,681 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन होता है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के 112 प्रोजेक्ट लगाए हैं। इसके अलावा, बायोफ्लोक के 257 प्रोजेक्ट लगाने के साथ-साथ चार कोल्ड स्टोरेज और 16 फीड मिल प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में नई किस्मों का उत्पादन करना चाहते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मुहैया करवाई जाए।

कृषि मंत्री ने 'प्रधानमंत्री संपदा योजना' की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह योजना मत्स्य किसानों विशेषकर झींगा पालकों के लिए एक वरदान है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि मत्स्य किसानों को खारे पाने में झींगा यूनिट स्थापित करने के लिए तय प्रोजेक्ट कीमत को पूर्व की भांति 25 लाख रुपए किया जाए। इस स्कीम को तटीय क्षेत्र में झींगा यूनिट स्थापित करने की तर्ज़ पर संपूर्ण भारत में विशेषकर हरियाणा प्रदेश में लागू किया गया, जबकि तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा प्रदेश में यूनिट स्थापित करने पर अधिक खर्च आता है। इसलिए मत्स्य पालकों को राहत देने हेतु प्रोजेक्ट की कीमत को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य के झींगा पालकों के लिए सोलर सिस्टम को प्रधानमंत्री संपदा योजना में शामिल कर उपलब्ध करवाने की बात भी कही ताकि मत्स्य पालकों का बिजली खर्च का बोझ कम हो सके और ऊर्जा के नए विकल्प मुहैया हो सकें।

**-संवाद ब्यूरो**

# पॉपलर के प्रमुख रोग एवं बचाव

पॉपलर पेड़ों को कई प्रकार के कीट और कीटाणु बाधित कर सकते हैं, जो पेड़ों के स्वास्थ्य और वृक्ष संपादन को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में पोपलर के प्रमुख कीट इस प्रकार हैः

**पॉपलर प्लॉटर बीटल :** यह प्रमुख कीट बीटल पेड़ों के बाल से प्रभावित होता है और पत्तियों को खाने के कारण पौधे की संरचना और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसका प्रबंधन करने के लिए प्रभावित भागों को हटा देना चाहिए और कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है।

**प्रबंधन :** कीट के अंडों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। दिसंबर में दो-तीन बार खेत की जुताई करें ताकि सर्दियों में मिट्टी और मलबे में प्यूपा बाहर आ जाए। दवाओं का छिड़काव करें।

**लीफ माइनर्स:** लीफ माइनर्स नामक छोटे कीट उगलदार कीट पत्तियों के भीतर खुदाई करते हैं और पत्तियों के स्वास्थ्य और वृक्ष प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। उनका प्रबंधन करने के लिए प्रभावित पत्तियों को हटा देना चाहिए और कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। कीटों का संक्रमण काल जुलाई-सितंबर होता है। पत्तियों पर धब्बे या फफोले के रूप में पहचाना जा सकता है। ।

**प्रबंधन:** इसके नियंत्रण के लिए 0.05% मोनोक्रोटोफॉस (अर्थात 1.4 मिली/लीटर पानी या 0.05% फॉस्फैमिडोन यानी 0.6 मिली/लीटर वाटर) का पूर्ण छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है।

**तना छेदक : प्रबंधन:** क्षेत्र की नियमित निगरानी। जैसे अन्य वैकल्पिक पोषक पौधों के रोपण से बचें। मुख्य तने में ग्रब के प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से शाखाओं की छंटाई करें। लोहे के तार को छेद में डालें और कीट को मार दें और छेद को मिट्टी से बंद कर दें।

**पॉपलर रूट बोरर:** यह कीट पेड़ की जड़ों में बोर करता है और पेड़ को खाता है, जिससे पेड़ का स्वास्थ्य और वृक्ष संरचना प्रभावित होती है। इसके प्रबंधन के लिए प्रभावित भागों को काट देना और उपयुक्त कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है।

### पॉपलर के प्रमुख रोग

**कैंकर:** यह वायरसीय रोग होता है जो पोपलर की छाल को आक्रांत करता है। कैंकर के कारण पेड़ की छाल फटने लगती है और प्रभावित हिस्से मर जाते हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए संक्रमित हिस्से को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए।

**तरकेवाला कीट:** तरकेवाले कीट भी पोपलर पेड़ों को प्रभावित कर सकते हैं और पत्तियों को खा सकते हैं, जिससे पेड़ का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उच्च दीमक गतिविधि वाले क्षेत्रों में, जहां क्षति बहुत व्यापक है और विकास को प्रभावित करने की संभावना है, रासायनिक उपचार निम्नानुसार किया जा सकता हैः

**छाल उपचार:** छाल या पेड़ के तने के बाहरी हिस्से पर दीमक के हमले को रोकने के लिए, 0.2% क्लोरपायरीफॉस या एंडोसल्फान के साथ ब्रश पेंटिंग या पेड़ के आधार पर उपचार के बाद मिट्टी के प्लास्टर या दीर्घाओं को खुरच कर किया जा सकता है।

**पॉपलर सैवा गाइड मोथ :** यह कीट पत्तियों को खाता है और पेड़ के वृक्ष संरचना को प्रभावित करता है। खेत को साफ़ रखें और वैकल्पिक मेज़बान को खेत के पास से हटा दें। नर्सरी चरणों में लार्वा को चुनकर मार दें।

**पॉपलर जंग रोग:** यह रोग पॉपलर की पत्तियों पर प्रमुखतः प्रकट होता है। इसके कारण पत्तियों पर सफेद या स्वर्ण रंग के गुच्छे बन जाते हैं और पत्तियों का गिरने का प्राकृतिक नियमित समय पर विघटन हो जाता है। इसे रोकने के लिए संक्रमित पौधों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए और सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

**ब्राउन स्पॉट:** यह रोग पोपलर की पत्तियों पर प्रकट होता है और पत्तियों पर भूरे रंग के दागों के रूप में पहचाना जा सकता है। यह रोग मौसम के बदलाव और पर्यावरणीय तत्वों के कारण होता है। इसका प्रबंधन करने के लिए संक्रमित पत्तियों को हटा देना चाहिए और स्वच्छता का ख़ास ख्याल रखना चाहिए।

**झुलसा रोग :** इसका प्रकोप अगस्त व सितंबर में देखा जाता है। यदि इसका हमला दिखे तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बेनडाज़िम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।

**जड़ सड़ांध :** छाल के नीचे और पेड़ के चारों ओर सफेद माइसीलियम की किस्में लंबी किस्में के रूप में। पेड़ के आधार पर फलने वाले शरीर या शहद के रंग के मशरूम जैसी संरचनाओं की उपस्थिति। पत्ती झुलसना, एकल बड़ी शाखाओं में शाखा सुखाने की शुरुआत। केंद्र में दिल की लकड़ी का सड़ना पेड़ के आधार/जड़ों/तने को चोट से बचाएं।

**अनिल कुमार (कृषि विज्ञान केंद्र, यमुनानगर), ममता खेपड, मोनिका जांगड़ा (वानिकी विभाग, प्रीति वर्मा, पौध रोग विभाग,चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार)**

मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा फंड नियमों के लिए गठित फंड प्रबंधन समिति की बैठक में राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की।

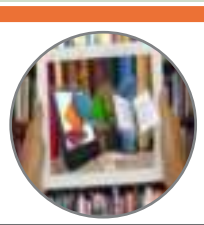

प्रदेश में अभी कुल एक हजार ई-लाइब्रेरी का निर्माण करवाया का चुका है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की युवा शक्ति को मिल रहा है।

# जी-20 साइबर सुरक्षा पर मंथन

साइबर खतरों से निपटने के लिए जी-20 की बैठक में विशेषज्ञों के मध्य गंभीर मंथन हुआ। गुरुग्राम में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में जी- 20 देशों, नौ विशेष आमंत्रित देशों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी लोगों, भारत और दुनियाभर के डोमेन विशेषज्ञों सहित 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार की डॉक्युमेंट्री को देखा जिसमें हरियाणा में हुए पुलिस सुधार, पंचकूला में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, साइबर हेल्पलाइन 1930, 318 साइबर हेल्प डेस्क, 29 साइबर पुलिस स्टेशन सहित अपराध की रोकथाम व सुरक्षा जैसे विषयों के बारे में विस्तार से दर्शाया गया। गृह मंत्री ने हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आमजन की सुरक्षा को लेकर उठाये गए कदमों को उल्लेखनीय बताया और कहा कि जनसेवा की दिशा में हरियाणा सरकार अपनी प्रभावी जिम्मेदारी निभा रही है। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार की स्टॉल पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और हरियाणा सरकार की कार्यशैली को अनुकरणीय बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेज़ी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेज़ीलिएन्स स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी आज सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल और आर्थिक सीमाओं के पार पहुंच चुकी है और आज हम एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज में रहते हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा - वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। गृह मंत्री ने कहा कि आज 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है और 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। अमित शाह ने कहा कि साथ ही साइबर खतरों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। उन्होंने इन्टरपोल की वर्ष 2022 की 'ग्लोबल ट्रेंड समरी रिपोर्ट' को उद्धत करते हुए कहा कि रैनसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन-शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृतियां विश्वभर में गंभीर खतरे की स्थिति पैदा कर रही हैं और ऐसी आशंका है कि भविष्य में ये साइबर अपराध कई गुना और बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जी- 20 ने अब तक आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा फ्लो पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब क्राइम और सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स को समझना और समाधान निकालना बेहद आवश्यक है।

## साइबर अपराध रोकने के लिए हरियाणा के प्रयास

- हरियाणा सरकार द्वारा मई 2023 तक 1,130 जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 3 लाख 15 हज़ार लोगों ने लाभ उठाया।
- सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देने के लिए 5,388 पोस्ट डाली गई हैं जिससे 2 लाख 66 हज़ार लोगों तक पहुंचते हुए उन्हें साइबर अपराध संबंधित गतिविधियों से बचाव को लेकर जागरूक किया गया।
- हरियाणा सरकार द्वारा 318 साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए गए जिनमें 700 बहु प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।
- संबंधित शिकायतों का तत्परता से निवारण करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एमरजेंसी रिस्पांस स्पोर्ट सिस्टम डायल 112 शुरू किया गया।
- प्रदेश में 29 साइबर पुलिस थाना ने 350 से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए।
- पंचकूला में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई।
- स्टेट क्राइम ब्रांच तथा सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से साइबर क्राइम संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए 3,566 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- स्टेट नोडल अथॉरिटी द्वारा एसओपी निर्धारित की गई है।
- साइबर अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता लाने को लेकर प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

# ग्रामीण विकास में नाबार्ड का विशेष सहयोग

विशेष प्रतिनिधि

नाबार्ड का देश की ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाबार्ड के सहयोग से हरियाणा कई क्षेत्रों में देश का नंबर वन राज्य बना है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को स्व रोजगार के लिए पशुपालन व्यवसाय के लिए एंकर के रूप में नाबार्ड आगे आए, इसमें हरियाणा सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी की गारंटी देने को तैयार है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि जब हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग राज्य बना था, उस समय तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। परंतु यहां के मेहनती किसान व कर्मचारियों ने नाबार्ड के सहयोग से हरियाणा को कई क्षेत्रों में अग्रणी बनाया है। नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए पूंजी उपलब्ध करवाई है। नाबार्ड द्वारा प्राइमरी कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण करने के कार्य की सराहना की।

### मछली पालन

नाबार्ड के अधिकारियों को कहा कि हरियाणा में लगभग 7-8 लाख एकड़ जमीन क्षारीय है तथा 2 लाख एकड़ भूमि खारे पानी वाली है। इस प्रकार 10 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य नहीं है। इस भूमि का उपयोग मत्स्य पालन व झींगा पालन इत्यादि के लिए किया जा सकता है। हरियाणा सरकार व नाबार्ड दोनों मिलकर कार्य करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से लगभग 100 करोड़ रुपए का झींगा का निर्यात होता है।

### जैविक किसान उत्पादक समूह

जिस प्रकार नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवा रहा है, उसी तर्ज पर जैविक किसान उत्पादक समूह का गठन करने में भी नाबार्ड आगे आए। गुरुग्राम व दिल्ली में जैविक कृषि उत्पादों की अधिक मांग है। प्रदेश सरकार एनसीआर में जैविक मंडी स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है। जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। दक्षिणी हरियाणा में मोटा अनाज बाजरा का अधिक उत्पादन होता है। सरकार द्वारा 2500 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है। गेहूं व धान के फसल चक्र से किसानों को अन्य फसलों की ओर ले जाने में नाबार्ड आगे आए।

### 13 हजार करोड़ के ऋण उपलब्ध

नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती दीपा गुहा ने बताया कि नाबार्ड ने इस वर्ष हरियाणा राज्य को 13 हजार करोड़ रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए ग्रामीण आधारभूत संरचना, 4700 करोड़ रुपए दीर्घकालीन ऋण तथा 6800 करोड़ रुपए फसली ऋण के लिए उपलब्ध करवाए हैं।

नाबार्ड द्वारा प्रदेश की 730 पैक्स में से 710 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। 661 पैक्स के लिए 4.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पैक्स से नाबार्ड तक ऑनलाईन प्रक्रिया की जा रही है। 28 राज्यों में नाबार्ड के नियमों को अपनाया है, उनमें हरियाणा भी एक है। अब पैक्स को बहुउद्देशीय संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, एलपीजी, पेट्रोल, हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग संवाददाता, सीएससी इत्यादि 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।

नाबार्ड द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जींद, रेवाड़ी तथा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक को संयुक्त देयता समूह के लिए अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके तहत 4 महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकेगा।

## किसानों को सबसे ज़्यादा मुआवज़ा

मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दस साल की सरकार या उससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं, उन सब सरकारों यानी जब से हरियाणा बना है तबसे सब से ज्यादा पिछले 8.5 साल में हमारी सरकार ने मुआवज़ा किसानों को दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 5,600 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। इस साल के अंत तक सभी 6,200 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंच जाने का अनुमान है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश मे अकेला राज्य है जहां किसानों के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

हरियाणा सरकार धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने के लिए किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दे रही है। इसी प्रकार, जो किसान डीएसआर तकनीक से धान की बिजाई करते हैं, उन्हें भी 4 हजार रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जा रही है।

हरियाणा सरकार गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी स्थापित कर रही है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस मंडी का सालाना कारोबार 30 से 40 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, रोहतक में जल्द ही उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

पंचकूला में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू होगा। कैंपस के लिए भूमि की तलाश के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

# जीओ गीता ऐप का शुभारंभ

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जीओ गीता ऐप के गीता जीवन गीत के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश विश्व के कोने-कोने तक पहुंचेंगे। इन गीता उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए जीओ गीता 23 दिसंबर 2023 गीता जयंती के दिन तक सवा करोड़ अष्टादशी श्लोकी गीता पाठ का लक्ष्य पूरा करेंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र में जीओ गीता की तरफ़ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने जीओ गीता ऐप गीता जीवन गीत का लोकार्पण किया।

### गीता को शिक्षा के साथ जोड़ना जरूरी

राज्यपाल ने जीओ गीता ऐप का लोकार्पण कर गीता का संदेश विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाने का सफल प्रयास करने जा रहे है। इस गीता जीवन गीत वैश्विक महा अभियान का मूल उद्देश्य घर घर में ही गीता के ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके विश्व में शांति सद्भाव का वातावरण तैयार करना है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता को शिक्षा के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गीता ज्ञान संस्थानम में जल्द की सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे है। इन कोर्स को शुरू करने की घोषणा एक दो दिनों तक कर दी जाएगी। इस पावन धरा पर भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। यह उपदेश पूरी मानव जाति के लिए आज भी प्रासंगिक है।

### ऐप से गीता का प्रचार-प्रसार

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि गीता के प्रचार-प्रसार के लिए एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। इस कार्य में उनका नेटवर्क अहम भूमिका अदा करेगा और हर प्रकार का सहयोग करेंगा। इन गीता उपदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर भरसक प्रयास किए जाएंगें। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि जीओ गीता ने ऐप तैयार करके एक अद्भुत कार्य किया है। इस छोटे से प्रयासों से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आमजन तक सहजता से पहुंच पाएंगें। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की सोच के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग गीता के उपदेशों को जन जन पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

# सावन का विशेष मिष्ठान्न घेवर

सावन आए और घेवर न आए, यह कम से कम उत्तर भारत में तो संभव नहीं है। घेवर, सावन का विशेष मिष्ठान्न माना जाता है। श्रीकृष्ण को समर्पित होने वाले 56 भोगों में घेवर का भी स्थान है। घी से भरपूर होने के कारण संस्कृत में इसे घृतपूर कहा गया है। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार पिष्टपूर, घृतवर, घार्त्तिक भी इसके पर्याय हैं। इनमें घृतवर से घेवर की व्युत्पत्ति अधिक निकट लगती है, घृतवर, घीवर , घेवर। गुजराती में घेबर (घ्यारी, घारी भी), मराठी में घेवर/घीवर, सिन्धी घीउरू, बांग्ला घ्योर आदि घेवर के ही नाम हैं।

सावन में सारे उत्तर भारत के बाज़ारों में घेवर छा जाता है। गलियाँ महकने लगती हैं। शायद ही कोई मिठाईवाला हो जो घेवर न रखता हो। घेवर लोक संस्कृति से भी जुड़ा है। तीज से लेकर रक्षाबंधन तक शायद ही कोई त्यौहार हो जिसमें घेवर का आदान-प्रदान न होता हो। बहू के मायके से उसके ससुराल वालों को घेवर भेजे जाने की प्रथा है। विवाह सगाई आदि रस्मों में घेवर की उपस्थिति अनिवार्य होती थी।

नई पीढ़ी में इसे कम पसंद किया जाता है किंतु खाने को मिल जाए तो वे भी इसके स्वाद की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। इसे स्वीट डिश या पुडिंग के तौर पर अपनाने वालों ने इसके शहद जैसे स्वाद और मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति के कारण इसका अंग्रेजी नामकरण कर दिया है- हनीकूम डिज़र्ट। कहीं-कहीं, विशेषकर कट्टर शाकाहारी परिवारों में, जन्मदिन के अवसर पर केक के बदले घेवर का उपयोग भी देखा गया है।

नए ज़माने में आज घेवर का रूप, आकार और स्वाद भी परिवर्तित होने लगा है। ग्राहकों की रुचि के अनुसार चीनी, घी की मात्रा भी घटाई-बढ़ाई जाने लगी है। अपने नाम से भिन्न घी रहित खस्ता घेवर भी बनने लगा है। कहते हैं पुराने ज़माने में घेवर की आकृति बारह इंच तक भी होती थी, किंतु अब घटकर कुछ इंच तक सिमट आया है।

घेवर में प्रयुक्त होने वाली मूल्यवान सामग्री मेवा, केसर, घी आदि के कारण बाज़ार में बहुत महँगा घेवर भी मिलता है जिसका मूल्य दो-ढाई हज़ार रुपए प्रति किलो हो सकता है। सामान्य उपभोक्ता के लिए चार-पाँच सौ से लेकर हजार-बारह सौ रुपए प्रति किलो का घेवर हाट में उपलब्ध है, जो जैसा दाम लगाने में सक्षम हो उसे उसी प्रकार का घेवर मिल जाता है। सादा घेवर सस्ता है जबकि पिस्ता, बादाम और मावे वाला महँगा। पिस्ता बादाम और मावे वाला घेवर अधिक प्रचलित हैं, यद्यपि लोगों का कहना है कि जितना आनन्द सादे घेवर में है उतना मेवे-मावे वाले घेवर में नहीं। तो खाइए घेवर और मनाइए सावन।

**-सुरेश पन्त**

## हास्य नाटक

# गई भैंस पाणी में

जिंदगी में हंसना बेहद जरूरी है। बिना हास्य के जीवन नीरस हो जाता है। एक ओर जहां हास्य तनाव को दूर करता है, वहीं लोगों के अंदर स्फूर्ति भी पैदा करता है। ऐसे में कलाकार जब हास्य के साथ सामाजिक संदेश लोगों तक पहुंचाते है और समाज को आईना दिखाते हैं, तो उनकी कला की सार्थकता सिद्ध होती है।

कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा कला परिषद के सहयोग से कुरुक्षेत्र में आयोजित हरियाणवी नाट्य उत्सव के दूसरे दिन न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप कुरुक्षेत्र के कलाकारों द्वारा हास्य नाटक गई भैंस पाणी में का मंचन किया गया। विकास शर्मा के लेखन और निर्देशन से सजे नाटक ने हास्य रस में लोगों को डुबकियां लगवाते हुए बड़े ही रोचक ढंग से साइबर क्राइम से बचने का संदेश दिया।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर एवं महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल के दिशा-निर्देश में आयोजित उत्सव में भरतमुनि रंगशाला में नाटक गई भैंस पाणी में शुरु से अंत तक लोगों को गुदगुदाने में कामयाब रहा।

नाटक में एक ऐसे परिवार में घटित घटना को दिखाया गया जो लालच में आकर गरीब बनने का ढोंग करते हुए साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। नत्थू और फुल्लो का बेहद अमीर परिवार है, जिसमें उनके दो बेटे और एक बहन भी साथ रहती है। एक दिन एक साईबर ठग गांव की भोली-भाली जनता को गुमराह करके अमीर बनाने का सपना दिखा देता है। जिसके कारण फुल्लो और उसका परिवार अमीर होते हुए भी गरीब बनने का ढोंग करते है।

परिवार का प्रत्येक सदस्य हास्य और हाजिर जवाबी के अंदाज में अपने-अपने ढंग से साइबर ठग को अपनी गरीबी का प्रमाण देता है। अंत में साइबर ठग साइबर 'क्राइम के जरिए नत्थू के परिवार के तीस हजार रुपए ठग लेता है। बाद में उसे पुलिस पकड़ लेती है, और नत्थू के परिवार को साइबर क्राइम के बारे में सचेत करती है। इस प्रकार हंसी के फव्वारे के साथ कलाकार लोगों को साइबर ठगी से बचने की सलाह देते हैं। नाटक में एक ओर जहां कलाकारों का अभिनय काबिले तारीफ रहा, वहीं नाटक की मंच सज्जा ने भी नाटक की खूबसूरती बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई।

नाटक का निर्देशन विकास शर्मा का रहा, वहीं नत्थू के किरदार में गौरव दीपक जांगड़ा, फुल्लो निकेता कौशिक, भतेरी ज्योति बांकुरा, चतर सिंह फण्डी शिव कुमार किरमच, कालू चंचल शर्मा, अमरु अमरदीप जांगड़ा, रमलू निखिल पारचा, पुलिस राजीव कुमार, जैल सिंह तुषार, सिपाही पार्थ शर्मा तथा चौकीदार जतिन बने। वहीं संगीत संचालन पर आकाशदीप व प्रकाश व्यवस्था पर लालचंद और रूपसज्जा रजनीश भनौट की रही।

**- संवाद ब्यूरो**

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com